ISSN : 2395-4132

THE EXPRESSION

An International Multidisciplinary e-Journal

Bi-Monthly Refereed & Indexed Open Access e-Journal

Impact Factor 3.9

Vol. 3 Issue 6 Dec. 2017

Editor-in-Chief : Dr. Bijender Singh

Email : editor@expressionjournal.com

www.expressionjournal.com

The Expression: An International Multidisciplinary e-Journal
(A Peer Reviewed and Indexed Journal with Impact Factor 3.9)
www.expressionjournal.com ISSN: 2395-4132

झुग्गी–झोपड़ी एवं सामान्य जीवन

जसनदीप सिंह,
शोधकर्ता तांतिया विश्वविद्यालय, गंगानगर
एवं
डॉ कालूराम,
शोध निदेशक, तांतिया विश्वविद्यालय, गंगानगर

Abstract

हमारे देष में झुग्गी–झोपड़ी और गंदी बस्ती की समस्या अत्यन्त गंभीर है। लोगों की बुरी आर्थिक दशा के कारण यह बढ़ती हुई जनसंख्या, उन्नत तकनीकी और धीमी प्रगति से होने वाले औद्योगिकीकरण का ही परिणाम है। भारत में झुग्गी जनसंख्या–झोपड़ी जनसंख्या का मतलब केवल गरीबी रेखा के नीचे स्थित झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से है। औद्योगिक प्रगति के बाद आज श्रमिकों के आवास की व्यवस्था अच्छी नहीं है। उन्हें गंदी बस्तियों में ही रहना पड़ता है। अतः वर्तमान युग में गंदी बस्तियों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। सस्ती कम लागत वाली आवास की कमी और गरीब नियोजन, झुग्गी बस्तियों की आपूर्ति पक्ष को प्रोत्साहित करती है। यदि समय रहते हुए झुग्गी–झोपड़ी और गंदी बस्ती के ही समस्या को दूर करने के लिए उचित कदम नहीं उठाये गये तो भयावह परिणाम सामने आएंगे।

Key-Words

झुग्गी–झोपड़ी, औद्योगिकीकरण, शहरी नियोजन, झोपड़ी जनसंख्या, शहरी प्रवास, मलिन बस्तियां

The Expression: An International Multidisciplinary e-Journal
(A Peer Reviewed and Indexed Journal with Impact Factor 3.9)
www.expressionjournal.com ISSN: 2395-4132

झुग्गी–झोपड़ी एवं सामान्य जीवन

जसनदीप सिंह,
शोधकर्ता तांतिया विश्वविद्यालय, गंगानगर
एवं
डॉ कालूराम,
शोध निदेशक, तांतिया विश्वविद्यालय, गंगानगर

मानव जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं–'भोजन, वस्त्र और आवास। पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वस्त्र तथा साफ–सुथरा आवास मानव की कार्यक्षमता एवं जीवन को सुचारू रूप से सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम एवं वांछनीय आवश्यकताएं हैं। वर्तमान युग मशीनीकरण का युग है। औद्योगिकीकरण के जितने भी आयाम हैं, सब मशीन पर निर्भर हैं, लेकिन इन मशीनों की कार्यक्षमता को बनाये रखने अथवा अनुकूल दशाओं के विकास के लिए श्रमिकों का संतुलित एवं पौष्टिक आहार शरीर ढूंढने को पर्याप्त मात्रा वस्त्र और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्यकर आवास की उपलब्धि नितान्त आवश्यक हैं। लेकिन औद्योगिक प्रगति के बाद आज श्रमिकों के आवास की व्यवस्था अच्छी नहीं है। उन्हें गंदी बस्तियों में ही रहना पड़ता है। अतः वर्तमान युग में गंदी बस्तियों की समस्या बनती जा रही है। सस्ती कम लागत वाली आवास की कमी और गरीब नियोजन, झुग्गी बस्तियों की आपूर्ति पक्ष को प्रोत्साहित करती है।[1]

जहां तक भारत जैसे विकासशील देश का प्रश्न है, झुग्गी–झोपड़ी और गंदी बस्ती की समस्या यहां अत्यधिक गंभीर है। लोगों की बुरी आर्थिक दशा के कारण यह बढ़ती हुई जनसंख्या, उन्नत तकनीकी और धीमी प्रगति से होने वाले औद्योगिकीकरण का ही परिणाम है। भारत में झुग्गी जनसंख्या–झोपड़ी जनसंख्या का मतलब केवल गरीबी रेखा के नीचे स्थित झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से है। जैसा कि भारत अभी भी विकास के रास्ते पर है, वहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

बहुत से लोग हैं ये लोग आमतौर पर शहर से जुड़े झुग्गी क्षेत्रों में रहते हैं। सरकारी स्रोतों के अनुसार, भारत की झोपड़ी जनसंख्या ब्रिटेन की जनसंख्या से अधिक है। पिछले दो दशकों में यह दोगुनी हो गई है। 2001 की अंतिम जनगणना के मुताबिक, भारत की झोपड़ी–आबादी की जनसंख्या 1981 में 27.9 मिलियन से बढ़कर 2001 में 61.8 मिलियन हो गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले चार वर्षों में सालाना 8 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोगों में करीब 1.1 अरब अभी भी एक दिन में 1 डॉलर (लगभग 46 रुपये) पर रहता है।[1]

औद्योगिक विकास के साथ भारत में झुग्गी जनसंख्या वृद्धि में हुई है। नए घरों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद, झुग्गी इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास बिजली, पानी की आपूर्ति और रसोई गैस नहीं है।

भारत में झोपड़ी जनसंख्या

मुंबई में झुग्गी जनसंख्या– भारत की आर्थिक राजधानी, मुंबई के रूप में जाना जाता है, अनुमानित 6.5 मिलियन झुग्गी बस्तियों का घर है। मुंबई की करीब 55 प्रतिषत आबादी झुग्गी इलाकों में रहती है।[1]

दिल्ली में झोपड़ी जनसंख्या– मुंबई के बाद, दिल्ली में भारत में दूसरी सबसे बड़ी झोपड़ी जनसंख्या है। भारत की राजधानी में लगभग 1.8 मिलियन लोग झुग्गी क्षेत्रों में रहते हैं। ये लोग ज्यादातर बेरोजगार या दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक हैं जो जीवन की बुनियादी जरूरतों को भी नहीं खरीद सकते हैं।

भारत के अलावा विष्व के कई देशों में मलिन बस्तियां मौजूद हैं और एक वैश्विक घटना बन गई है। संयुक्त राष्ट्र–आवास रिपोर्ट में कहा गया है कि 2006 में लगभग 1 अरब लोग लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश शहरों में झोपड़पट्टी बस्ती में व्यवस्थित थे, और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के शहरों में एक छोटी संख्या थी। 2012 में, यूएन–आवास के अनुसार, विकासशील दुनिया में 863 मिलियन लोग मलिन बस्तियों में रहते थे। इनमें से शहरी झुग्गी आबादी उप–सहारा अफ्रीका में लगभग 213 मिलियन, पूर्वी एशिया में 207 मिलियन, दक्षिण एशिया में 201 मिलियन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 113 मिलियन, दक्षिण पूर्व एशिया में 80 मिलियन, 36 मिलियन पश्चिम एशिया, और उत्तरी अफ्रीका में 13 मिलियन अलग–अलग देशों में, शहरी निवासियों के अनुपात में 2009 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य (95.9 प्रतिषत), चाड (89.3प्रतिषत), नाइजर (81. 7प्रतिषत), और मोजाम्बिक (80.5प्रतिषत) में सबसे अधिक था। कई शहरों में, ग्रामीण और शहरी प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या के लिए पर्याप्त कम लागत वाले आवास प्रदान नहीं करते हैं। कुछ

ग्रामीण–शहरी प्रवासी श्रमिक शहरों में आवास नहीं खरीद सकते हैं और अंततः केवल सस्ती मलिन बस्तियों में बैठ सकते हैं। इसके अलावा, मुख्य रूप से 'षहरों ऊंची आय के लालच में ग्रामीण प्रवासियों की शहरों में बाढ़ जारी है। वे इस प्रकार मौजूदा शहरी झुग्गी बस्तियों का विस्तार करते हैं।[2]

कुछ विद्वानों का मानना है कि शहरीकरण झुग्गी बस्ती पैदा करता है क्योंकि स्थानीय सरकारें शहरीकरण का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं, और प्रवासियों को सस्ती जगह पर रहने के लिए, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। रैपिड शहरीकरण आर्थिक विकास को गति देता है और लोगों को शहरी क्षेत्रों में काम करने और निवेश के अवसर तलाशने का कारण बनता है। हालांकि, जैसा कि गरीब शहरी बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त आवास के रूप में प्रमाणित है, स्थानीय सरकार कभी–कभी इस संक्रमण का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं। कुछ मामलों में, शहरीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय सरकारें आप्रवासियों के प्रवाह को अनदेखा करती हैं।

कौशल और शिक्षा और प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजारों की कमी के कारण कई झुग्गी बस्तियों में बेरोजगारी की उच्च दर का सामना करना पड़ता है। गंदी बस्तियों में अपराध मुख्य चिंताओं में से एक है। अनुभवजन्य आंकड़े बताते हैं कि सामान्य जीवन की तुलना में झुग्गी बस्तियों में अपराध की दर अधिक होती है।[1]

झुग्गी निवासियों को आमतौर पर एचआईवी, एड्स, 4, खसरा, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दवा प्रतिरोधी तपेदिक और कई अन्य घातक रोगों और महामारियों का सामना करना पड़ता है। सामान्य क्षेत्रों की तुलना में बाल कुपोषण अधिक मलिन बस्तियों में आम है। ताडा एट अल द्वारा बैंकाक की झोपड़–पट्टी में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि वहां पर लगभग 8 प्रतिषत बच्चे कुपोषण से पीड़ित थे। इथियोपिया और नाइजर में शहरी झुग्गियों में बाल कुपोषण की दर लगभग 40 प्रतिषत है।

हाल के वर्षों में मलिन बस्तियों की संख्या में नाटकीय वृद्धि देखी गई क्योंकि विकासशील देशों में शहरी आबादी में वृद्धि हुई है। दुनिया भर में करीब एक अरब लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, और यह संख्या 2030 तक 2 अरब तक बढ़ सकती हैं, अगर सरकारें और वैश्विक समुदाय झुग्गी बस्ती को नजरअंदाज करते हैं और शहरी नीतियां जारी रखती हैं। तो इसके भयावह परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र आवास समूह का मानना है कि परिवर्तन संभव है। झुग्गियों के बिना शहरों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि सरकारें शहरी नियोजन, शहर प्रबंधन, ढांचागत विकास, झोपड़ी उन्नयन और गरीबी कम करने के लिए जिम्मेदार हैं।[1]

झुग्गीकरण स्थानांतरण रणनीति मलिन बस्तियों को हटाने और शहरों को अर्ध–ग्रामीण परिधि मुक्त करने के लिए झोपड़ी गरीबों को स्थानांतरित करने पर भरोसा देती हैं। यह रणनीति एक मलिन बस्ती जीवन के कई आयामों पर ध्यान नहीं देती है। रणनीति झुग्गी झोपड़ी को केवल एक जगह के रूप में देखती है जहां गरीबों की जिन्दगी होती है। वास्तव में, झुग्गी बस्ती अक्सर एक झोपड़ी निवासी के जीवन के हर पहलू के साथ एकीकृत होती हैं, जिसमें रोजगार के स्रोत, काम से दूरी और सामाजिक जीवन शामिल है। झुग्गी पुनर्वास जो आजीविका कमाने के अवसरों से गरीबों को विस्थापित करता है, गरीबों में आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न करता है। कुछ मामलों में, झुग्गी निवासियों ने स्थानांतरित करने का विरोध किया है, भले ही शहर के बाहरी इलाके में प्रतिस्थापन भूमि और आवास स्वतंत्र और उनके वर्तमान घर की तुलना में बेहतर गुणवत्ता है।[1]

आज की दुनिया में से कुछ झुग्गियां उपनिवेशवाद द्वारा लाए गए शहरीकरण का एक उत्पाद हैं। उपनिवेशवादियों द्वारा लगाए गए अलगाव की वजह से अन्य का निर्माण किया गया था। उदाहरण के लिएए मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती आज भारत में सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक है।

भारत में भविष्य की झोपड़ी जनसंख्या

हाल के अनुमानों के मुताबिक, 2017 तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी झोपड़ी आबादी का हिस्सा होगा। ये राज्य पहले ही बड़ी संख्या में झोपड़ी की आबादी वाले घर हैं, जो ज्यादातर शहरी इलाकों में और आसपास रहते हैं। 2017 तक, भारत में 20 मिलियन से अधिक झोपड़ी आबादी वाला घर होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान होगा। अनुमान है कि 2018 तक भारत की कुल झोपड़ी जनसंख्या 105 मिलियन होगी।

REFERENCES:

1. आधुनिक भारत, *कोलेष्वर राय 2012*
2. पुण्यभूमि भारत, *सुधामूर्ति 2009*
3. मुक्त भारत, *गुरुचरण दास 2013*
4. भारत में समाज, *मोतीलाल गुप्ता 2011*
5. भारतीय अर्थ व्यवस्था, *झुनझुनवाला, 2012*
6. भारतीय समाज, *डॉ सुनील त्यागी, 2014*
7. आधुनिक भारत, *सुमित कुमार, 2009*